वीर सावरकर जी का जीवन राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी उनकी भव्य प्रतिमा

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 - अंक : 09 - दिसंबर 2025

भारत ने सुरक्षा, अर्थतंत्र व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में बड़ी उपलब्धियां हासिल की

युवाओं के लिए अवसरों का केंद्र बन रही सहकारिता

सहकारी समितियों के सशक्तीकरण में प्रधानमंत्री की 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प की अहम भूमिका 22

वैश्विक कृषि में इफको नैनो फर्टिलाइजर की अफ्रीका तक बढ़ी मांग 27

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

दिसंबर 2025, अंक 09, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन

संपादक
राजीव शर्मा

समूह संपादक
वेद प्रकाश सेतिया

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें :
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com

प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।

निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली : 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते :

MINISTRY OF COOPERATION

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

आवरण कथा

08
युवाओं के लिए अवसरों का केंद्र बन रही सहकारिता
सहकारिता के माध्यम से युवाओं का भविष्य संवारने और उनके लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए-नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

12
भारत को नई आर्थिक दिशा देने वाला निर्णायक मंच बनकर उभरा है Earth Summit
शिखर-वार्ताओं का उद्देश्य केवल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर नए सिरे से विचार कर परिणाम-उन्मुख समाधान निकालना भी है।

वीर सावरकर जी का जीवन राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी उनकी भव्य प्रतिमा 14

वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन बन रहा भारतः श्री नरेन्द्र मोदी 16

किसानों के कल्याण की सक्षम शक्ति बनी डेयरी सहकारिता 18

'वंदे मातरम्' स्वतंत्रता, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का सबसे शक्तिशाली जयघोष : श्री अमित शाह 20

अगले पांच वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा बस्तर 24

'सहकार से समृद्धि' की राष्ट्रीय परिकल्पना वास्तविकता में हो रही परिवर्तित 26

28
पुणे की स्वच्छ सहकारी समिति ने दिखाई नई राह

ग्रामीण जीवन को सुगम बना रही सहकारिता

भारतीय गणराज्य में वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है और इसी का परिणाम है कि 'सहकारिता' आम जनमानस से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है। सहकारी संस्थाएं आजादी के पूर्व से ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर ग्रामीण क्षेत्र के विकास में प्रमुख योगदान दे रही हैं। सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल करती हैं और इस प्रकार इनमें जबरदस्त कार्य उत्पादक क्षमता है। भारत की अधिकांश ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहकारिता से प्रभावित होती है और किसी न किसी रूप में लगभग हर ग्रामीण जीवन को प्रभावित करती है। ग्रामीण परिवेश में यह 'जीवन की सुगमता' के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। आज सहकारिता देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होने के कारण हमेशा केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता रही है।

भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। आज देश आर्थिक विकास में नयी इबारत लिख रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था अब पांच ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था का स्वरूप लेने जा रही है। इस अर्थ यात्रा में सहकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान निश्चित है। सहकारी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में संगठित होने वाले किसान, उद्यमी, और उत्पादकों के साथ सहयोग करता है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का साधन उपलब्ध कराता है। देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिसके करीब 30 करोड़ सदस्य हैं जो मुख्यतः कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुधन, मत्स्य, चीनी, उर्वरक, वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्यान्न आदि के उत्पादन से जुड़े हुए हैं।

भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, सहकारिता तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों विनिर्माण, सेवाओं और कृषि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सहकारी समितियां किसानों को पूंजी, प्रौद्योगिकी और विपणन आउटलेट तक पहुंच प्रदान करके कृषि क्षेत्र में मदद कर रही हैं। साझा सुविधाएं और बाजारों तक पहुंच प्रदान करके छोटे विनिर्माण व्यवसायों के विस्तार में सहायक सिद्ध हो रही हैं। साथ ही आवास, चिकित्सा तथा परिवहन जैसी बेहतर सेवाएं प्रदान करने की ओर अग्रसर है। आर्थिक प्रगति में भाग लेने के लिए सहकारी समितियां शासन, प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपना रही हैं।

सहकारिता का लाभांश वितरण का सिद्धांत तथा सामाजिक जिम्मेदारी, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक गतिशीलता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ग्रामीण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर केंद्रित इसका बिजनेस माडल बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में सक्षम है।

सहकारिता, लैंगिक समानता को मजबूती प्रदान करते हुए महिलाओं की भूमिका को बढ़ा रहा है। साथ ही, हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाते हुए सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में सहकारी समितियां एक प्रभावी वाहक की भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही हाल ही में स्थापित तीन नई बहु राज्य सहकारी समितियां भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड तथा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को साकार करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कर चुकी है जो कि भारतीय सहकारिता एवं अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मील का पत्थर' साबित होगी।■

जय सहकार

हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। यह देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा। श्रमेव जयते!

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

पैक्स का आधुनिकीकरण हो, नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण हो, या त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की नींव रखना हो, मोदी सरकार में सहकारिता किसानों, पशुपालकों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही है और विश्वभर में भारतीय कोऑपरेटिव मॉडल का आदर्श स्थापित कर रही है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त व दूरदर्शी नेतृत्व एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकार से समृद्धि की राष्ट्रीय परिकल्पना, सशक्त वास्तविकता में परिवर्तित हो रही है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने भारत में वर्ष 2047 तक एक सर्वांगीण, विश्वस्तरीय सहकारिता प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक संस्थागत प्रोत्साहन और स्पष्ट रोडमैप प्रदान किया है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

पिछले चार वर्षों में गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण और दूरगामी नीतिगत निर्णय लागू किए गए हैं। सहकारिता व्यवस्था का मुख्य घटक प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) है और इन्हें अधिक सक्षम, आधुनिक तथा बहु-क्षेत्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

श्री मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

महिला नेतृत्व वाली डेयरी सहकारी समितियां ग्रामीण भारत में सकारात्मक परिवर्तन की प्रमुख संवाहक बन रही हैं। यह समितियां आर्थिक अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के साथ दूध उत्पादन, विपणन, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाकर समग्र विकास को गति दे रही हैं। महिलाएं अब मात्र सहयोगी नहीं, बल्कि ग्रामीण प्रगति की अग्रणी शक्ति हैं, जो सिद्ध करती हैं कि संगठित महिला नेतृत्व पूरे समुदाय के विकास को सक्षम बनाता है।

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

नई ऊंचाइयों और प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है देश: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र 2025 से पहले मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि राष्ट्र की तीव्र प्रगति की चल रही यात्रा के लिए नई ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 'यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह सत्र राष्ट्र की प्रगति में तेजी लाने के लिए वर्तमान में चल रहे प्रयासों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।' प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन सत्र 2025 के आरंभ से पूर्व मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं की जीवंतता और भावना का प्रदर्शन किया है। हाल ही में हुए बिहार चुनावों का उदाहरण देते हुए, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी की सराहना की और इसे राष्ट्र की लोकतांत्रिक शक्ति का एक प्रबल प्रमाण बताया।

महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि यह एक उल्लेखनीय और उत्साहजनक प्रवृत्ति है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नई आशा और नया विश्वास लाती है। जैसे-जैसे भारत के लोकतांत्रिक संस्थान मजबूत हो रहे हैं, दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार राष्ट्र की आर्थिक क्षमताओं को भी सुदृढ़ कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 'भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र सफल परिणाम दे सकता है।' 'जिस गति से भारत की आर्थिक स्थितियाँ नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, वह नया विश्वास जगाती है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमें नई शक्ति देती है।'

भारत ने यह सिद्ध किया है कि लोकतंत्र सफल परिणाम दे सकता है- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे सत्र को राष्ट्रीय हित, रचनात्मक चर्चा और नीति-आधारित परिणामों पर केंद्रित रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद को इस बात पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए कि वह राष्ट्र के लिए क्या कल्पना करती है और राष्ट्र के लिए क्या करना चाहती है। विपक्ष से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सार्थक और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दलों को आगाह किया कि वे चुनावी हार की निराशा को संसदीय कार्यवाही पर हावी न होने दें। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सत्र में चुनावी जीत से उपजा अहंकार भी नहीं झलकना चाहिए। शीतकालीन सत्र में संतुलन, जिम्मेदारी, और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित गरिमा दिखनी चाहिए।

संसद सदस्यों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जो अच्छा काम हो रहा है उन्हें और बेहतर बनाया जाए और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ रचनात्मक और सटीक आलोचना प्रस्तुत की जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर जानकारी मिल सके। 'यह मेहनत का काम है, लेकिन राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है।'

पहली बार संसद पहुंचे युवा सांसदों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कई अलग-अलग पार्टियों के कई सांसद महसूस करते हैं कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने या राष्ट्रीय विकास की चचाओं में योगदान देने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि इन सांसदों को वह मंच मिले जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा, 'सदन और राष्ट्र, दोनों को नई पीढ़ी की समझ और ऊर्जा से लाभ मिलना चाहिए।'

संसद नीति और परिणामों के लिए है न कि ड्रामा या नारेबाजी के लिए। 'ड्रामा करने या नारेबाजी के लिए अन्य जगहों की कोई कमी नहीं है। ■

अहमदाबाद में ₹1500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण कर बोले श्री अमित शाह

भारत ने सुरक्षा, अर्थतंत्र व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में बड़ी उपलब्धियां हासिल की

सहकार जागरण टीम

- **प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सभ्यता, संस्कृति व सनातन धर्म का समूचे विश्व में सम्मान बढ़ा**
- **गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क, धोलेरा में बन रही एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सिटी**

गुजरात आज दिन-दूनी, रात-चौगुनी प्रगति कर रहा है, जहां हम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को पूरे भारत में सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इन संकल्पों को अहमदाबाद नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास के दौरान व्यक्त किया। 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के माध्यम से 58 विकास योजनाओं को एक ही मंच से संपन्न करते हुए श्री शाह ने कहा कि विकास का कोई आयाम अछूता नहीं है। राज्य में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में शुरू की गई विकास यात्रा को श्री भूपेन्द्र पटेल ने पूरी गति और समर्पण से आगे बढ़ाया है।

विश्व का सबसे बड़ा 'रिन्यूएबल एनर्जी पार्क' गुजरात में बन रहा है और एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सिटी भी धोलेरा में बन रही है। गुजरात से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे 'सूरत-चेन्नई एक्सप्रेस-वे' शुरू होता है। गिफ्ट सिटी के रूप में भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल हब भी हमारे गुजरात में ही है। देश की पहली बुलेट ट्रेन 'अहमदाबाद-मुंबई' यहीं से शुरू होगी और पहली नमो रैपिड रेल 'भुज से अहमदाबाद' भी राज्य में ही चलेगी।

श्री शाह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1370 मकानों का लोकार्पण किया, जिनमें थलतेज क्षेत्र में 861 और वासना क्षेत्र में 509 आवास जरूरतमंद लोगों को दिए गए। उन्होंने नारनपुरा क्षेत्र में झुग्गी पुनर्विकास के तहत बने मकानों का लोकार्पण और ड्रॉ भी किया। श्री शाह ने बापल क्षेत्र के 'इलेक्ट्रोथर्म गार्डन' और रानीप के 'स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर' का भी शुभारंभ किया।

कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी करेगा अहमदाबाद

अहमदाबाद में तीन स्थानों पर नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमिपूजन कर श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद शहर में अनेक आधुनिक खेल-संकुल बन चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के सभी खेलों और कोचिंग की बेहतरीन व्यवस्था हो चुकी है। 70 से ज्यादा देशों की खेल सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं में खेल के प्रति लगाव और रहने-खाने

की सुविधाओं की तुलना करने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी भारत को मिली है। श्री शाह ने कहा कि 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स' भी अहमदाबाद में होंगे। 13 अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाएं अहमदाबाद में आयोजित होंगी, जिससे विश्व के खेल मानचित्र पर अहमदाबाद अग्रणी स्थान पर होगा। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के बाद ये सारी खेल सुविधाएं, स्टेडियम, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल बेकार नहीं जाएंगे, बल्कि पूरे विश्व में हर खेल के प्रशिक्षण का सर्वोत्तम केंद्र अहमदाबाद में बनेगा। अहमदाबाद में अब अगर किसी को खेलना हो तो घर से पांच किलोमीटर के दायरे में ही सारी सुविधाएं सुलभ हैं। मोटेरा में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 'नरेन्द्र मोदी स्टेडियम' है और उसके ठीक बगल में उससे भी भव्य सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनाने का कार्य शुरू हो चुका है।

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय गुजरात ने ही देश में सबसे 'खेलो गुजरात' की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य था कि युवा व्यसन, आलस्य और कु-संगत छोड़ें, खेल-कूद में भागीदारी बढ़ाएं और जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। 'खेलो गुजरात' से शुरू हुई यह यात्रा 'खेलो इंडिया' तक पहुंची और आज देश के सभी राज्यों में खेल-कूद को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने अयोध्या में 2019 में राममंदिर का भूमिपूजन किया, 2024 में प्राण-प्रतिष्ठा की और 2025 में भगवा ध्वज फहराकर पूरा काम सम्पन्न कर 'जय श्री राम' का उद्घोष किया। अयोध्या में भव्य राममंदिर बन चुका है और जहां सीता माता का जन्म हुआ था, वहां कुछ महीने पहले मंदिर का भूमिपूजन हो चुका है और 2026 तक वहां मंदिर निर्माण भी पूर्ण हो जाएगा।

'ग्रीन गांधीनगर' के लिए पांच पेड़ लगाने का लें संकल्प

श्री शाह ने कहा कि गांधीनगर की जनता को एक संकल्प लेना है कि बरसात में हर सोसाइटी में कम-से-कम पांच पेड़ जरूर लगाएं ताकि 'ग्रीन गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र' की शुरूआत हो सके। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। साफ हवा, सहनीय गर्मी, पक्षियों का कलरव और तनाव-मुक्त माहौल बनाने का एकमात्र उपाय वृक्षारोपण है। श्री शाह ने कहा कि पिछले पांच साल में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में ग्रीन एरिया में 13.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमें इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम हर सोसाइटी में पांच से 50 पेड़ लगवाएंगे और वहां के युवाओं को पानी देने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। श्री शाह ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में ब्रिज और ओवरब्रिज के नीचे जहां पहले सिर्फ. गंदगी और अंधेरा था, वहां अब छोटे-छोटे सुंदर खेल-संकुल, लाइब्रेरी, योगासन की व्यवस्था और ओपन जिम बना दिए गए हैं। उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि सभी को अहमदाबाद आकर जगह का सदुपयोग सीखना चाहिए। ■

भारत को विश्व की महान शक्ति बनाने का संकल्प

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर भारत का डंका बजने जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। देश की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है और अर्थतंत्र को मजबूती मिली है। पूरे देश में चारों ओर हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। जनकल्याण के कार्यों के जरिए देश में गरीबी उन्मूलन, गरीबों की सुविधाएं बढ़ाने, गांवों व शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और भारत को विश्व में उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार-व्यवसाय की अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। भारत ने अनाज उत्पादन में दोगुनी वृद्धि की है, सिंचाई क्षेत्र का लगभग दोगुना विस्तार हुआ है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न की खरीद में तीन गुना बढ़ोत्तरी हुई है। इसका असर यह है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म समूचे विश्व में सम्मान के साथ पहचाना जा रहा है। श्री मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने भारत को विश्व की महान शक्ति बनाने का संकल्प स्वीकार कर लिया है।

युवाओं के लिए अवसरों का केंद्र बन रही सहकारिता

- सहकारिता से युवाओं को जोड़ने पर बल
- प्रोफेशनल ट्रेनिंग व रोजगार को सहकारिता से प्रोत्साहन मिल रहा
- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सहकारिता से युवाओं को जोड़ने के दिए सुझाव

सहकार जागरण टीम

सहकारिता के माध्यम से युवाओं का भविष्य संवारने और उनके लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए-नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। सहकारिता को अर्थव्यवस्था की बुनियाद का प्रमुख हिस्सा बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। देश में सहकारिता का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत अथवा बेहद छोटे समूहों के उत्थान के लिए किया जाता रहा था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसके लिए एक व्यापक विस्तार का मसौदा तैयार किया है। इस बाबत न सिर्फ रोजगारन्मुखी नीतियां बनाई जा रही हैं, बल्कि नए-नए क्षेत्रों में संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बाद सहकारिता क्षेत्र युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का एक बड़ा माध्यम है। हालांकि, सहकारी क्षेत्र में युवाओं की मांग को पूरा करने के लिए युवाओं की बड़ी दरकार है। युवाओं के लिए अभी तक यह क्षेत्र उनका करियर नहीं बन पा रहा है। खासकर, सहकारी समितियों में नेतृत्व स्तर पर युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए पहल की गई है। युवाओं को इससे जोड़ने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, देश में पहली बार त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से युवाओं को कोऑपरेटिव की शिक्षा एवं प्रशिक्षण को मजबूती मिलेगी। यह यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को पूरा करेगी।

सहकार की भावना हमारे देश में नई नहीं है। इसका समावेशन हमारी संस्कृति में सदियों से है। वसुधैव कुटुम्बकम का भारत का जो नारा है वह सहकार का ही एक प्रतिबिंब है और सहकारिता इसका एक रूप है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के छह स्तंभों में

2030
तक कोऑपरेटिव में युवाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय करने को उठाए जाएं कदम

5,000
से ज्यादा युवा नेतृत्व वाली कोऑपरेटिव्स की स्थापना की जाए

10
लाख से ज्यादा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएं

60
प्रतिशत शिक्षित युवाओं में कोऑपरेटिव के बारे में जागरूकता पैदा की जाए

500
से ज्यादा ऑनलाइन कोऑपरेटिव स्थापित करना भी हो लक्ष्य

युवाओं को सहकारिता से जोड़ने और सहकारिता के माध्यम से उनका भविष्य संवारने के उपाय किए गए हैं। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि इस बात की संपूर्ण समीक्षा की जाए कि युवाओं को आगे बढ़ाने के क्या उपाय किए गए हैं, कोऑपरेटिव्स के लीडरशिप में उनकी कितनी भूमिका है, सहकारी संस्थाओं के निदेशक मंडल में उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, बोर्ड में शामिल युवा निदेशकों का गवर्नेंस कैसा है, उनके लिए जिम्मेदारी तय की जाती है या नहीं। इस तरह की समीक्षा नहीं की जाएगी तो न तो यह क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा और न ही युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि भारत युवाओं का देश है, जिससे में अपार संभावनाएं हैं। उन्हें सहकारिता क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए नई नीति की जरूरत है। इसी के मद्देनजर नई सहकारिता नीति तैयार की गई है, जिसके छह स्तंभ हैं। इन सभी स्तंभों का उद्देश्य युवाओं को आकर्षित करने के लिए कोऑपरेटिव्स में उनकी सहभागिता बढ़ाने के उपाय किए गये हैं। कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे युवाओं का भविष्य संवारा जा सकता है, इसे भी देखना पड़ेगा और उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव्स उनके लिए कैसे लाभदायक हैं। युवाओं को कोऑपरेटिव सेक्टर से कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए इस क्षेत्र में क्या-क्या संभावनाएं मौजूद हैं, इन सब मुद्दों पर आधारित एक प्रेजेंटेशन हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से दिया गया है जिसमें इन समस्याओं के समाधान के तरीके बताए गए हैं। 'नौकरी चाहने वालों से लेकर परिवर्तन लाने वालों तकः सहकारी समितियों में युवाओं को प्रोत्साहित करना' विषय पर आधारित इस प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि युवाओं को सहकारी क्षेत्र से जोड़ने के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए। साथ ही इसमें कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इन लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक कोऑपरेटिव में युवाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना, पूरे देश में 5,000 से ज्यादा युवा नेतृत्व वाली कोऑपरेटिव्स की स्थापना, 10 लाख से ज्यादा रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, 60 प्रतिशत शिक्षित युवाओं में कोऑपरेटिव के बारे में जागरूकता पैदा करना और 500 से ज्यादा ऑनलाइन कोऑपरेटिव स्थापित करना शामिल है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संयुक्त सचिव डॉ. कमल कुमार त्रिपाठी ने कहा, 'यह कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बहुत महत्व समय है। आज युवाओं में सहकार की भावना तो है, लेकिन वे सहकारिता क्षेत्र से दूर चले गए हैं। उनको सहकारी सिद्धांतों के माध्यम से इस क्षेत्र में लाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें समझाना और जागरूक करना होगा कि आखिर यह है क्या और इस क्षेत्र में वे अपना करियर कैसे बना सकते हैं? एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से ही इस क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कुशल पेशेवरों को तैयार किया जा सकता है। सहकारिता राज्य का विषय है। राज्यों को भी इसे बढ़ावा देने के लिए काफी सुधार और मेहनत करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कई राज्यों में नया कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए मेंबर्स की संख्या 50 तक होना जरूरी है। जम्मू-कश्मीर में तो 100 सदस्यों की अनिवार्यता है। इसी तरह, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा सभी राज्यों में नहीं है, जबकि अब हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं। इस तरह के कई प्रावधानों में राज्य स्तर पर बदलाव की जरूरत है।

सहकारिता के पांच ई मॉडल

सहकारिता क्षेत्र में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए वैश्विक सहकारी संगठन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायांस (आईसीए) ने 'पांच ई मॉडल' एजुकेशन, इम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटीज, इंगेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने की जरूरत है। एजुकेशन एवं ट्रेनिंग और मानव संसाधन के लिए नीति बनाने, टेक्नोलॉजी को अपनाने जैसे उन्हें उपाय करने होंगे।'

सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण

युवाओं को सहकारिता क्षेत्र से जोड़ने के लिए सबसे पहले सहकारी शिक्षा क्षेत्र को

विकसित करने की जरूरत पर जोर देना होगा। हालांकि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर इसी के मद्देनजर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल पेशेवर तैयार करने के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज स्तर पर इसकी पढ़ाई को लेकर भी सुझाव देगी और नीतियां बनाएगी। यह यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र के लिए युवा एवं योग्य श्रमबल की स्थायी और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, कौशल संबंधी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मौजूदा कौशल विकास केंद्रों एवं संस्थानों के साथ तालमेल बिठाएगी, सहकारी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम व अध्ययन सूची तैयार करने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास का संचालन करेगी और प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया है कि सहकारिता को एक विषय के रूप में स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाए। बीए, बीकॉम, एग्रीकल्चर, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम आदि में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाया जाए। यूपीएससी एवं राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में सहकारिता को भी एक विषय के रूप में शामिल किया जाए। सहकारिता क्षेत्र की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। सहकारिता को पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने के अलावा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कोऑपरेटिव स्टोर, कोऑपरेटिव कैंटीन एवं क्रेडिट सोसायटी बनाई जाए। इससे छात्र न सिर्फ इस क्षेत्र के काम करने के तरीकों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि उनमें सहकार की भावना भी मजबूत होगी।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन

शिक्षा के साथ युवाओं के लिए रोजगारपरक नीतियां होनी चाहिए। उचित शिक्षा के बाद युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलेगा तो वह इसे कभी भी करियर के रूप में नहीं अपनाएंगे। इसके लिए जरूरी है उन्हें प्रशिक्षण देने की। युवाओं को नौकरी

> मोदी सरकार का लक्ष्य देश में एक ऐसा कोऑपरेटिव एनवायरमेंट बनाना है जिसमें युवा अच्छी से अच्छी शिक्षा लेकर कोऑपेरिटिव को अपना करियर बनाएं। भारत का मूल विचार एक ऐसा मॉडल बनाने का है जिसमें सबका सामूहिकता के साथ विकास हो, सबका सम विकास हो और सभी के योगदान से देश का विकास हो।
>
> - श्री अमित शाह
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

सुरक्षित करने और फाइनेंस एवं टैक्स का प्रबंधन करने का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाना भी बेहद जरूरी है। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग कोऑपरेटिव में काम करने के लिए तकनीकी दक्षता की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया है कि जहां सामाजिक सुरक्षा कमजोर है, वहां सहायता प्रणाली प्रदान की जाए। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए कौशल और नई उद्यम गतिविधियों का विकास किया जाए और साझा स्वामित्व एवं सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न रूपों वाले कामगार तैयार किए जाएं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, कोऑपरेटिव इनक्यूबेटर की संख्या बढ़ाने, इनोवेटिव इंटरप्रेन्योरशिप की पूंजी तक पहुंच बढ़ाने, उन्हें सहयोगात्मक कानूनी ढांचा मुहैया कराने, समुदाय में व्यापार करने में आसानी हो इसके लिए सहयोग देने जैसे सुझाव दिए गए हैं।

अन्य उपायः युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए सहकारी युवा ब्रांड तैयार करने और उन ब्रांडों के साथ युवाओं का जुड़ाव बनाने की भी जरूरत महसूस की गई है। साथ ही युवाओं का नेटवर्क तैयार करने, उनमें स्वामित्व की भावना पैदा करने, उन्हें महत्वपूर्ण नवाचार उपलब्ध कराने, युवा ऊर्जा और अनुभवी एवं प्रतिबद्ध भावी नेताओं का समूह तैयार करने पर भी जोर दिया गया है।

युवा कैसे होंगे आकर्षित

जागरूकताः युवाओं को सहकारी समितियों की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा के साथ-साथ उनमें जागरूकता बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए युवा केंद्रित अभियानों का आयोजन किया जाए। युवा सहकारी नेताओं की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया, प्रभावशाली व्यक्तियों और कहानी सुनाने के साधनों का उपयोग किया जाए। 'यूथ कोऑपरेटिव एम्बेस्डर' कार्यक्रम बनाएं जाएं और सहकारिता के प्रति जागरूकता एवं रुचि बढ़ाने के लिए इससे जुड़े लोग अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें।

आधुनिकीकरण और नवाचार अपनानाः सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण, उनके द्वारा नवाचार अपनाए जाने और डिजिटल सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से भी युवा इस ओर आकर्षित होंगे। आईटी, ई-कॉमर्स, नवीकरणीय ऊर्जा या रचनात्मक उद्योगों में युवा नेतृत्व वाले

सहकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना भी इसके लिए जरूरी है। आज की डिजिटल दुनिया में डिजिटल टूल्स को अपनाए बगैर युवाओं को आकर्षित करना मुश्किल है। आज की युवा पीढ़ी को हर चीज ऑनलाइन चाहिए। उनकी इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियां ऑनलाइन सदस्यता प्रणाली, मोबाइल ऐप और ई-गवर्नेंस को अपना कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ सकती हैं। कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल पर केंद्रित इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं के नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है।

फाइनेंस एवं सपोर्ट सिस्टम तक पहुंचः इसके तहत युवा केंद्रित सहकारी ऋण योजनाएं शुरू करने की जरूरत है ताकि युवा नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को स्टार्टअप अनुदान या कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध करवाया जा सके। युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन करने के लिए पहले से स्थापित सहकारी समितियां व्यवसाय सलाहकारों के साथ साझेदारी करें ताकि उन्हें परामर्श एवं प्रशिक्षण दिया जा सके। युवा सहकारी समिति शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान और तेज बनाने का भी सुझाव सलाहकार परिषद ने दिया है।

प्रतिनिधित्व और नेतृत्वः कोऑपरेटिव सोसायटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोऑपरेटिव यूनियन एवं फेडरेशन में युवा प्रतिनिधियों की भागादीरी बढ़ाने के लिए युवाओं की सीट आरक्षित की जाए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया है कि कोऑपरेटिव यूनियनों में अलग से यूथ विंग की स्थापना की जाए ताकि यूनियनों में युवाओं का इंगेजमेंट बढ़े और उन्हें लीडरशिप ट्रेनिंग मिल सके।

सामाजिक और पर्यावरणीय फोकसः युवाओं को आकर्षित करने के सुझावों में सहकारी समितियों को युवा मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने की भी वकालत की गई है। उन्हें स्थिरता, समावेशिता और सामुदायिक प्रभाव के मुद्दों पर जोर देने का सुझाव दिया गया है जो युवा पीढ़ी को जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने कि लिए सहकारी समितियों को स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था या लैंगिक समानता जैसे सतत विकास लक्ष्यों से निपटना जरूरी है।

कोऑपरेटिव के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़ना जरूरी है। युवा न सिर्फ ऊर्जा से भरपूर होते हैं, बल्कि उनके पास नए विचार, आधुनिक एवं नया कौशल, डिजिटल कौशल होता है और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जोश एवं उत्साह भरा रहता है जो किसी भी कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। साथ ही ये सहकारी समितियों की पीढ़ीगत निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय चुनौतियों से निपटने, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समावेशन और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी ये मददगार हैं। जोखिम लेने से घबराना नहीं और अनिश्चितताओं के प्रति उनका अलग दृष्टिकोण रखना भी एक महत्वपूर्ण कारक जिसकी वजह से उन्हें कोऑपरेटिव से जोड़ना देश के विकास के लिए लाभदायक साबित होगा।■

नई सहकारिता नीति में युवाओं को जोड़ने की रणनीति

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में सहकारी क्षेत्र को पेशेवर, सशक्त और नवाचार की दिशा में आगे ले जाने का खाका प्रस्तुत किया गया है। यह नीति न केवल सहकारी संस्थानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर केंद्रित है, बल्कि इसमें युवाओं को सहकारिता क्षेत्र से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस नीति के केंद्र में दो प्रमुख पहल हैं। सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक सर्वोच्च संगठन का निर्माण और सहकारी आंदोलन में युवा पीढ़ी को शामिल करने के लिए एक व्यापक रणनीति। नई नीति के तहत युवाओं को सहकारी उद्यमों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सहकारिता से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल से दक्ष बनाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि युवाओं को सहकारी प्रणाली से जोड़ने और उनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष संस्था की स्थापना की जाएगी, जो राज्य स्तरीय सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय कर भविष्य के लिए नेतृत्व तैयार करेगी, जिससे सहकारी संस्थाओं का संचालन अधिक पेशेवर रूप से किया जा सके। यह शीर्ष संस्था पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक नियुक्ति और मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाओं का मानकीकरण करेगी। साथ ही, समाज विज्ञान में डिग्री व डिप्लोमा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को सहकारिता से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर देश में पहली बार त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इस नीति के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए एक संगठित तंत्र विकसित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित या वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण की व्यवस्था और पहुंच बेहतर हो सके। इसके अलावा, सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही, नए और उभरते क्षेत्रों में सामाजिक उद्यम इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण और सामुदायिक स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे। नई नीति में राष्ट्रीय डिजिटल सहकारी रोजगार एक्सचेंज की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो योग्य उम्मीदवारों और सहकारी संस्थाओं के बीच सीधा और पारदर्शी संपर्क सुनिश्चित करेगा। साथ ही, एक राष्ट्रीय शिक्षक और प्रशिक्षक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने Earth Summit 2025 का किया उद्घाटन

भारत को नई आर्थिक दिशा देने वाला निर्णायक मंच बनकर उभरा है Earth Summit

सहकार जागरण टीम

- **सहकारी भावना पर आधारित सहकार टैक्सी आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी टैक्सी सेवा बनेगी**
- **प्रत्येक पंचायत में गठित होगा पैक्स, जीडीपी में सहकारिता का योगदान तिगुना करने का लक्ष्य**
- **'सहकार सारथी' के साथ 13 डिजिटल सेवाएँ लॉन्च**
- **नाबार्ड द्वारा विकसित 'सहकार सारथी' सहकारी बैंकिंग को करेगा डिजिटल रूप से सशक्त**

शिखर-वार्ताओं का उद्देश्य केवल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर नए सिरे से विचार कर परिणाम-उन्मुख समाधान निकालना भी है। गुजरात में आयोजित Earth Summit-2025 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यह समिट ग्रामीण भारत को आर्थिक दिशा देने वाला निर्णायक मंच बनकर उभरा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सहकारिता क्षेत्र के योगदान को तीन गुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पैक्स गठित किया जा रहा है। Earth Summit में श्री शाह ने 13 से अधिक डिजिटल सेवाएं लांच की। उन्होंने कहा कि नाबार्ड द्वारा विकसित सहकारी सारथी ग्रामीण बैंकिंग को डिजिटल रूप से सशक्त करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को अब विश्व स्तरीय डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होंगी।

श्री शाह ने कहा कि यह दूसरी शिखर-वार्ता देशभर में आयोजित की जा रही तीन अर्थ-समिट की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन तीनों समिट के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े चार मंत्रालयों के बड़े मुद्दों के समाधान तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष दिल्ली में होने वाली

तीसरी समिट में सभी विमर्शों का एक सुसंगत नीति की रुपरेखा प्रस्तुत की जाएगी।

महात्मा गांधी के कथनों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि उन्होंने कहा था कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसके विकास की परिकल्पना गांवों को केंद्र में रखे बिना संभव नहीं है। लेकिन आजादी के कुछ वर्षों बाद ही हम इस मंत्र को भूल बैठे। कृषि, पशुपालन और सहकारिता, ग्रामीण विकास के तीनों प्रमुख स्तंभ लंबे समय तक उपेक्षित रहे। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाने का ऐतिहासिक परिवर्तन शुरू हुआ।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के साथ तय किया है कि आने वाले वर्षों में देश की प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी संस्था स्थापित की जाएगी। सहकारिता के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएँगे। इससे सहकारिता क्षेत्र का जीडीपी में योगदान वर्तमान की तुलना में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब यह लक्ष्य पूरे होंगे तब कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटेगा। चाहे वह पशुपालन करने वाली ग्रामीण महिला हो अथवा देश के छोटे किसान।

गुजरात में सहकारिता में सहकार मॉडल के माध्यम से हजारों करोड़ की लो-कॉस्ट डिपॉज़िट बढ़ी हैं। अब मार्केट, डेयरियाँ, पैक्स और सभी कोऑपरेटिव्स जिला कोऑपरेटिव अम्ब्रेला से एकीकृत हैं। उन्होंने कहा कि सभी कोऑपरेटिव संस्थाओं के खाते और बचत कोऑपरेटिव बैंक में ही रखने का मॉडल लागू किया गया है। इससे लो-कॉस्ट डिपॉज़िट में भारी वृद्धि हुई। कोऑपरेटिव सेक्टर की क्रेडिट क्षमता पाँच गुना बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि इस समिट के माध्यम से गुजरात और बनासकांठा मॉडल पर चलते हुए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की पूरी क्षमता को 100 प्रतिशत उपयोग में लाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जा रही है।

सहकारिता में तकनीक के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि इसके बिना सहकारिता आगे नहीं बढ़ सकती है। छोटी कोऑपरेटिव्स के पास टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का भार उठाने की क्षमता नहीं थी। नाबार्ड ने 'सहकार सारथी' के माध्यम से सभी ग्रामीण बैंकों को 13 से अधिक डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। सभी जिला केंद्रीय, राज्य, कृषि और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक ही टेक्नोलॉजी अम्ब्रेला के दायरे में आएंगे। आधुनिक बैंकिंग तकनीक बिना किसी आर्थिक बोझ के उपलब्ध होगी। वसूली, डिस्बर्समेंट, केवाईसी , लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अप्रेजल, वेबसाइट निर्माण आदि पूरी तरह टेक-इनेबल होंगे और ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंकों में रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लागू होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पैक्स के सहयोग से एक मजबूत सहकारी बैंकिंग ढांचा खड़ा किया जा रहा है। जल्दी ईकेसीसी रखने वाले किसान विश्व के महंगे क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएँ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

श्री शाह ने कहा कि अब राष्ट्रीय स्तर पर तैयार सहकारी डेटा के आधार पर जहां-जहां वैक्यूम है, वहाँ विस्तार की योजना बनाई जाएगी। जरूरत वाले गाँव/क्षेत्र की पहचान सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत हो सकेगी। पिछले दो वर्षों से चल रहे प्रोजेक्ट में बचे हुए वैज्ञानिक सुधार अगले वर्ष पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात ने डेयरी सेक्टर में पूर्ण सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल स्थापित कर लिया है। उत्पादों का स्वदेशीकरण हो चुका है। किसानों को सीधे लाभ पहुंच रहा है। अब इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है।

श्री शाह ने कहा कि देश में इस समय लगभग 49 लाख किसान सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उत्पाद बना रहे हैं। भारत ऑर्गेनिक्स और अमूल ऑर्गेनिक्स के साथ राष्ट्रीय स्तर की लैब चेन स्थापित हो रही है। 40 से अधिक ऑर्गेनिक खाद्य वस्तुएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि 2035 तक विश्व ऑर्गेनिक मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बहुराज्यीय कोऑपरेटिव्स किसानों से उत्पाद खरीदकर टेस्टिंग के बाद वैश्विक बाजार में निर्यात करेंगे और इसका लाभ सीधे किसानों के खाते में जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर 'सहकार टैक्सी' लॉन्च की गई है और केवल ट्रायल में ही 51,000 ड्राइवर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आने वाले समय में यह देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव टैक्सी कंपनी बनेगी। टैक्सी ड्राइवर ही उसके मालिक होंगे। सहकार टैक्सी सहकारी समिति में होने वाले लाभ में ड्राइवर बराबर के हिस्सेदार होंगे।■

वीर सावरकर जी की कविता 'सागरा प्राण तळमळला' के 115 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन

वीर सावरकर जी का जीवन राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी उनकी भव्य प्रतिमा

- आयोजन स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने वाला ऐतिहासिक क्षणः डॉ. मोहन भागवत
- प्रेरणा पार्क और वीर सावरकर जी की प्रतिमा अडिग रहकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा करने की दिशा में भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगीः श्री अमित शाह

सहकार जागरण टीम

वीर सावरकर जी की कविता 'सागरा प्राण तळमळला' के 115 वर्ष पूर्ण होने पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्रीविजयपुरम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवकर संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और केंद्रीय गृह एंव सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। इस अवस पर उन्होंने वीर सावरकर जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण और प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह आयोजन स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने वाला ऐतिहासिक क्षण है। संघ प्रमुख ने कहा 'सावरकर जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वह महाराष्ट्र या अमुक जाति के हैं। वास्तववव में उस (आजदी) समय देश के लिए मरने की जरूरत थी और आज देश के लिए जीने की जरूरत है। नई पीढ़ी को उनके जीवन को समझना चाहिए। उन्हें जो रास्ता चुनना पड़ा उसे समझने की आवश्यकता है। उन्होंने साहस के साथ सब कुछ किया। हमें अपने बच्चों को दिशा देनी है।'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने इस अवसर पर कहा 'प्रेरणा पार्क और सावरकर जी की प्रतिमा उनकी ही भांति अडिग रहकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा तथा उनके स्वप्नों को साकार करने की दिशा में भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी'। उन्होंने वीर सावरकर के जीवन को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। गृह मंत्री ने एक्स पर

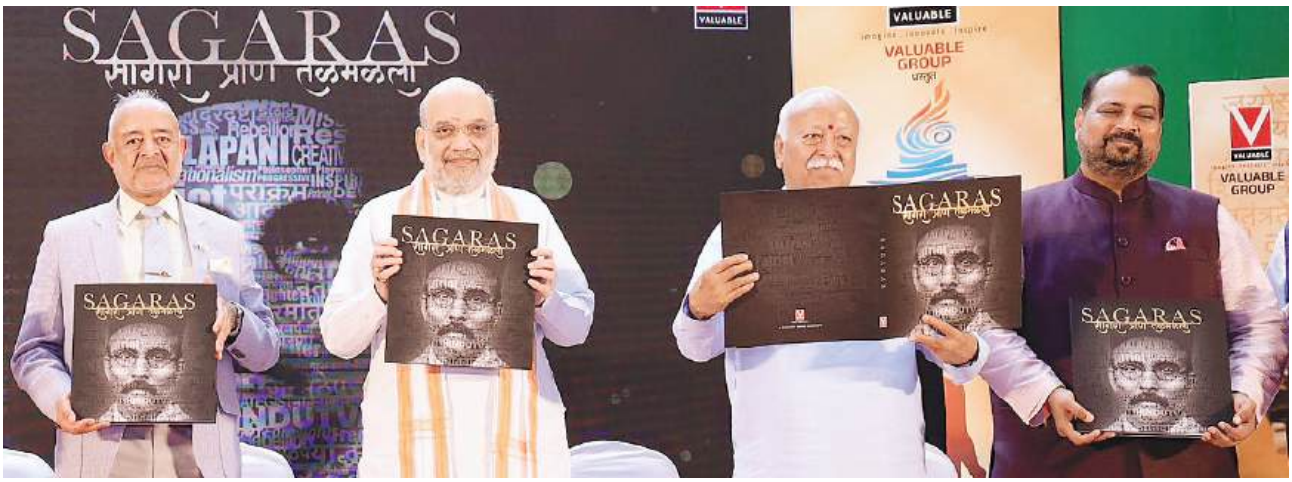

अपनी पोस्ट में लिखा कि 'वीर सावरकर जी का जीवन मातृभूमि के प्रति अथाह प्रेम और राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करेगा।'

इस पवित्र तपोभूमि पर वीर सावरकर जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण इसे चिरस्मरणीय बनाएगा। यह प्रतिमा उनके बलिदान, संकल्प और भारत माता के प्रति अखंड समर्पण का प्रतीक बनकर रहेगी और दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देगी। यह वीर सावरकर के साहस एवं मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता का संदेश देगा और दृढ़ता के उनके गुण, राष्ट्रीय एकात्मता, सुरक्षा और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को युवाओं को सौंपने का एक बहुत बड़ा स्थान बनेगा। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकरजी को वीर की उपमा किसी सरकार ने नहीं दी है बल्कि देश के जन जन ने दी है। दो उम्रकैद मिलने पर भी मातृभूमि के यशोगान के लिए साहित्य सृजन करने वाले सावरकर जी से बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चिंतन के आधार पर वीर सावरकर जी ने ही इसकी नींव रखी थी। श्री शाह ने कहा कि ऐसी सामूहिक पहचान जो भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और इतिहास से उपजती है, उसे जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, उनमें वीर सावरकर जी इसके सबसे प्रखर उपासक थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से भारत पर हमेशा के लिए गुलामी का बोझ और मानसिकता थोपने का प्रयास किया और इसीलिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को विप्लव कहा, लेकिन वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विप्लव की जगह उसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम देकर देश की सच्ची स्पिरिट को आगे बढ़ाया।

श्री शाह ने कहा कि देशभक्ति की अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा है वीर सावरकर जी की 'सागरा प्राण तळमळला'। उनका यह वाक्य उनके अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वीरता भय का अभाव नहीं, बल्कि भय पर प्राप्त की गई विजय है। वीर सावरकर जी ने इस वाक्य को जिया है कि जो भय को नहीं जानते वो हमेशा से वीर होते हैं, लेकिन सच्चे वीर वे होते हैं जो भय को जानते हैं और उसे परास्त करने का साहस रखते हैं। श्री शाह ने कहा कि यह वीर सावरकर जी द्वारा किए गए आह्वान को हमारे युवाओं द्वारा आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ शरीर से नहीं बनता है बल्कि जिस विचारधारा का वह अनुसरण करता है, आत्मा जिसे श्रेष्ठ मानती है। उस संस्कृति और व्यक्ति के कर्म से भी बनता है और वीर सावरकर जी के इन तीनों गुणों को सिर्फ भारत ही पहचान सकता है।

यहां कॉफी टेबल बुक के विमोचन के माध्यम से सावरकर जी के सभी गुणों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार सागर को कोई बांध नहीं सकता, उसी प्रकार सावरकर जी के गुणों और जीवन की ऊंचाई और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को पुस्तक, फिल्म या कविता में संजोकर रखना बेहद कठिन है। श्री शाह ने कहा कि अलग-अलग स्तर पर हुए कई प्रयासों ने आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी को समझने का बहुत बड़ा जरिया दिया है। उनका जीवन आधुनिक भी था और परंपराओं को साथ लेकर उनका वहन करने वाला भी था। अस्पृश्यता के निवारण के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, हमारे देश ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। सावरकर जी ने हिंदू समाज की सभी कुरीतियों के खिलाफ उस वक्त संघर्ष किया और समाज का विरोध झेलते हुए भी आगे बढ़े।

श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर जी ने आत्म बलिदान किया। उन्होंने कहा कि लेकिन, आज देश के लिए बलिदान देने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की जरूरत है और तभी सावरकर जी की कल्पना का भारत हम बना सकते हैं। सावरकर जी के जीवन को ध्यान से देखते हैं तो लगता है कि ऐसा व्यक्ति आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगा। श्री शाह ने कहा कि सावरकर जी एक राइटर, फाइटर, जन्मजात देशभक्त, बहुत बड़े समाजसुधारक, बहुत बड़े लेखक और कवि भी थे। वे गद्य और पद्य दोनों में सिद्धहस्त थे और ऐसे साहित्यकार बहुत कम हैं। श्री शाह ने कहा कि लगभग 600 से अधिक ऐसे शब्द हैं जो वीर सावरकर जी ने हमारी भाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे शब्दकोष में दिए हैं।■

नई दिल्ली में आयोजित एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री

वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन बन रहा भारत: श्री नरेन्द्र मोदी

सहकार जागरण टीम

- **मंदी, अविश्वास और विखंडन की दुनिया में भारत निभा रहा सेतु निर्माता की भूमिका**
- **भारत की नारी शक्ति अद्भुत काम कर रही है, आज बेटियां हर क्षेत्र में कर रहीं हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन**
- **हमारी गति स्थिर है, हमारी दिशा एकरूप है, हमारा इरादा हमेशा राष्ट्र प्रथम है**

अनिश्चितता के इस दौर में भारत आत्मविश्वास से भरकर एक अलग ही मुकाम पर पहुंच रहा है। जब दुनिया मंदी की बात करती है तो भारत विकास की कहानी लिखता है, जब दुनिया विश्वास के संकट का सामना करती है तो भारत विश्वास का स्तंभ बनता है, और जब दुनिया विखंडन की ओर बढ़ती है तो भारत एक सेतु-निर्माता के रूप में उभरता है। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास चालक बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किया।

पिछले एक दशक में भारत ने हासिल की असाधारण उपलब्धि

पिछले एक दशक में भारत की उपलब्धियों को असाधारण और देश में आए बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करने वाली बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह बुनियादी बदलाव लचीलेपन, समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने की प्रवृत्ति, आशंकाओं के बादल हटाने और आकांक्षाओं के विस्तार का है। यही कारण है कि आज का भारत न सिर्फ.खुद को बदल रहा है, बल्कि आने वाले कल को भी बदल रहा है। आज के सुधार और आज का प्रदर्शन कल के बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर, गांवों, टियर-2 और टियर-3 शहरों, नारी शक्ति, नवोन्मेषी युवाओं, समुद्री शक्ति और नीली अर्थव्यवस्था तथा अंतरिक्ष क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग किए जाने के दृष्टिकोण से भारत के काम करने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत में आधुनिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और उद्योग में अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। गांवों और छोटे शहरों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, छोटे शहर स्टार्टअप्स और एमएसएमई के नए केंद्र बन रहे हैं, और गांवों के किसान वैश्विक बाजारों से सीधे जुड़ने के लिए एफपीओ बना रहे हैं। भारत की नारी शक्ति उल्लेखनीय

उपलब्धियां हासिल कर रही है और देश की बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं। यह परिवर्तन अब केवल महिला सशक्तीकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की मानसिकता और ताकत दोनों को बदल रहा है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा निजी क्षेत्र

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने, इसके सुधार किए जाने और इसके परिणाम देश के सामने आने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रही है और उड़ान के लिए तैयार विक्रम-1 का विकास कर रही है। सरकार ने यह मंच प्रदान किया और भारत के युवा इस पर एक नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यही सच्चा परिवर्तन है।

हर क्षेत्र में सुधार होने, भारत की गति स्थिर होने, उसकी दिशा सुसंगत होने और उसका इरादा राष्ट्र प्रथम होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2025 सुधारों का वर्ष रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगली पीढ़ी का जीएसटी है। इस वर्ष प्रत्यक्ष कर प्रणाली में भी एक बड़ा सुधार पेश किया गया। सुधारों को जारी रखने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि लघु कंपनी की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप हजारों कंपनियां अब सरल नियमों, तेज प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं।

भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि चाहे जहाज निर्माण हो या रक्षा निर्माण, देश आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है। पहले छोटी-छोटी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था, लेकिन इसे बदलने के लिए जन-विश्वास कानून लाया गया। इसके माध्यम से ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया। मुद्रा योजना के माध्यम से अब तक 37 लाख करोड़ रुपए के गारंटी-मुक्त ऋण दिए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लोगों को हो रहा लाभ

भारत के बेहतर भविष्य के लिए उसके क्षितिज का विस्तार करने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश की भविष्य की जरूरतों को समझने और वर्तमान में समाधान खोजने की जरूरत है। इसीलिए वे अक्सर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना ने नागरिकों को ऊर्जा सुरक्षा अभियान में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर दिया है। अब लोग खुद बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और स्वंय की जरूरत से अधिक बिजली को बिजली कंपनी को बेचकर आर्थिक लाभ भी हासिल कर रहे हैं।

मोबाइल फोन के मामले में आयातक की जगह निर्यातक बना भारत

मोबाइल फोन के मामले में देश को आयातक की जगह एक प्रमुख निर्यातक होने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 11 साल पहले एक सुधार लागू किया गया। इससे देश ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब दुनिया इसके परिवर्तनकारी परिणाम देख रही है। कल को बदलने की यात्रा अनेक योजनाओं, नीतियों, निर्णयों, जन आकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह एक निरंतरता की यात्रा है, जो किसी शिखर सम्मेलन की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सभी का सहयोग और सामूहिक प्रयास आवश्यक है।■

गुजरात में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक

किसानों के कल्याण की सक्षम शक्ति बनी डेयरी सहकारिता

सहकार जागरण टीम

श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य है हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना और हर जिले में एक डेयरी की स्थापना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरूप डेयरी सहकारिता आज किसानों के विकास की सक्षम शक्ति बन चुकी है। सहकारिता भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की आय वृद्धि, महिला सशक्तीकरण और देश की दुग्ध आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन तथ्यों को गुजरात में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए साझा किया। राज्य के वाव-थराद जिले में बनास डेयरी में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत में हर महिला की आय बढ़ाने और हर घर को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम डेयरी सहकारिता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण स्तरीय मंडलियों को 'इंश्योरेंस कोऑपरेटिव्स' से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण समुदाय को बीमा सेवाओं तक सरल पहुंच मिलेगी। श्री शाह ने यह भी कहा कि डेयरी सहकारी समितियों को इंश्योरेंस के साथ जोड़ा जायेगा, जिससे गांव के लोगों को दोपहिया और चारपहिया वाहनों का बीमा सहकारिता के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने आह्वान किया कि सहकारी संस्थाएं अन्य सहकारी संस्थानों में भी निवेश करें, जिससे सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर मजबूती और पूंजी का विस्तार सुनिश्चित हो सके। सहकारिता तंत्र को और सशक्त करने के लिए उन्होंने नए सुझाव और दिशा-निर्देश भी दिए।

श्री शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं। इनके माध्यम से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है। इसका उद्देश्य हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने और पर्याप्त दूध उत्पादन होने पर हर जिले में एक डेयरी स्थापित करना है। यह एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि दुग्ध प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ साझेदारी कर आणंद में स्थापित त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (टीएसयू) बी.एससी और एम.एससी स्तर पर डेयरी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन का पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगी। इन विषयों के ग्रैजुएट अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देश भर के जिलों में बनास डेयरी के मॉडल को लागू करने में अपना योगदान देंगे। श्री शाह ने कहा कि किसान को उसके दूध का पूरा लाभ मिले, इसके लिए इस प्रयास को सफल बनाना होगा। बनास डेयरी की सफलता का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि देशभर के प्रत्येक जिले में चार अत्याधुनिक सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए किसानों को यह समझाना आवश्यक है कि कब, कौन-सा खाद–यूरिया, डीएपी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना उपयुक्त है। इससे मिट्टी स्वस्थ रहेगी और फसलों की उत्पादकता भी बढ़ेगी।

भारत की डेयरी सहकारिता क्षेत्र और श्वेत क्रांति 2.0 को लेकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा के दौरान संसदीय परामर्शदात्री समिति के समक्ष सहकारी डेयरी क्षेत्र पर एक व्यापक प्रस्तुति दी गई, जिसमें डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं तथा इसमें 'सर्कुलैरिटी और सस्टेनेबिलिटी' को बढ़ावा देने में सहकारी डेयरी समितियों की भूमिका को उजागर किया गया।■

स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है वंदे मातरम् : प्रधानमंत्री श्री मोदी

सहकार जागरण टीम

आजादी के पहले देश के महान नेताओं का सपना स्वतंत्र भारत का था, जबकि आज की पीढ़ी का सपना समृद्ध भारत का है। जिस तरह वंदे मातरम् की भावना ने स्वतंत्रता के स्वप्न को पोषित किया, उसी तरह यह समृद्धि के स्वप्न को भी पोषित करेगी। अगर आजादी से 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 2047 से 25 साल पहले हम भी एक समृद्ध और विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। इस मंत्र और संकल्प के साथ वंदे मातरम् हमें प्रेरित करता रहेगा, हमें हमारे ऋण की याद दिलाता रहेगा, अपनी भावना से हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा और इस स्वप्न को पूरा करने के लिए राष्ट्र को एकजुट करता रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा की शुरूआत करते हुए यह विचार व्यक्त किया।

वंदे मातरम् वह मंत्र और आह्वान है जिसने राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यही विचार भगवान श्री राम ने भी प्रतिध्वनित किया था, जब उन्होंने लंका के वैभव का त्याग करते हुए कहा था, 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'। वंदे मातरम् इस महान सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक अवतार है। वंदे मातरम् में हजारों वर्षों की सांस्कृतिक ऊर्जा समाहित है। इसमें स्वतंत्रता की भावना है और एक स्वतंत्र भारत का दृष्टिकोण भी निहित है। वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम दा ने इसके माध्यम से भारत के शक्तिशाली स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रचीं जो इस बात पर बल देती हैं कि भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी होने के साथ-साथ शत्रुओं पर शस्त्र चलाने वाली प्रचंड चंडिका भी हैं।

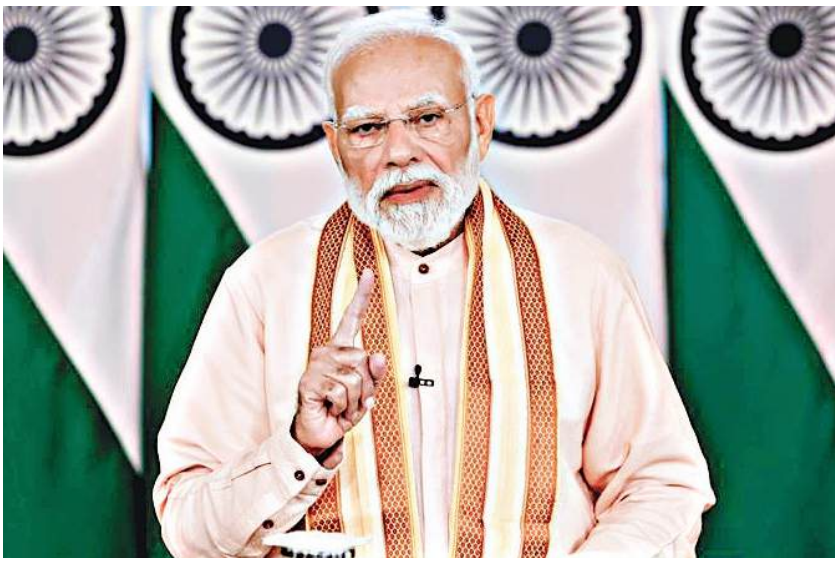

- वंदे मातरम् ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को दिया बल
- वंदे मातरम् ने हजारों वर्षों से गहराई से जड़े जमाए विचारों को फिर से किया जागृत

श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् ने लाखों देशवासियों को यह एहसास दिलाया कि स्वतंत्रता संघर्ष जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था, न ही केवल सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए था, बल्कि उपनिवेशवाद की जंजीरों को तोड़ने और महान परंपराओं, गौरवशाली संस्कृति और हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए था। वंदे मातरम् का जन-जन से गहरा जुड़ाव हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक लंबी गाथा के रूप में अभिव्यक्त हुआ। जब भी किसी नदी का उल्लेख होता है—चाहे वह सिंधु हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, गंगा हो या यमुना हो—वह अपने साथ संस्कृति की एक धारा, विकास का प्रवाह और मानव जीवन का प्रभाव लेकर आती है। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम का प्रत्येक चरण वंदे मातरम् की भावना से प्रवाहित हुआ और इसके तटों ने उस भावना को पोषित किया।

शहीद खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास और अनगिनत अन्य की शहादत को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों ने वंदे मातरम् को अपने होठों पर रखते हुए फांसी को गले लगा लिया। विश्व इतिहास में कहीं और ऐसी कोई कविता या गीत नहीं मिलता जिसने सदियों से लाखों लोगों को एक ही लक्ष्य के लिए प्रेरित किया हो और उन्हें अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया हो, जैसा कि वंदे मातरम् ने किया था। वंदे मातरम स्वतंत्रता का मंत्र है, त्याग का मंत्र है, ऊर्जा का मंत्र है, पवित्रता का मंत्र है, समर्पण का मंत्र है, त्याग और तपस्या का मंत्र है, और वह मंत्र है जिससे कष्ट सहने की शक्ति मिली। जैसे-जैसे हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं, वंदे मातरम् हमारी प्रेरणा बना हुआ है।■

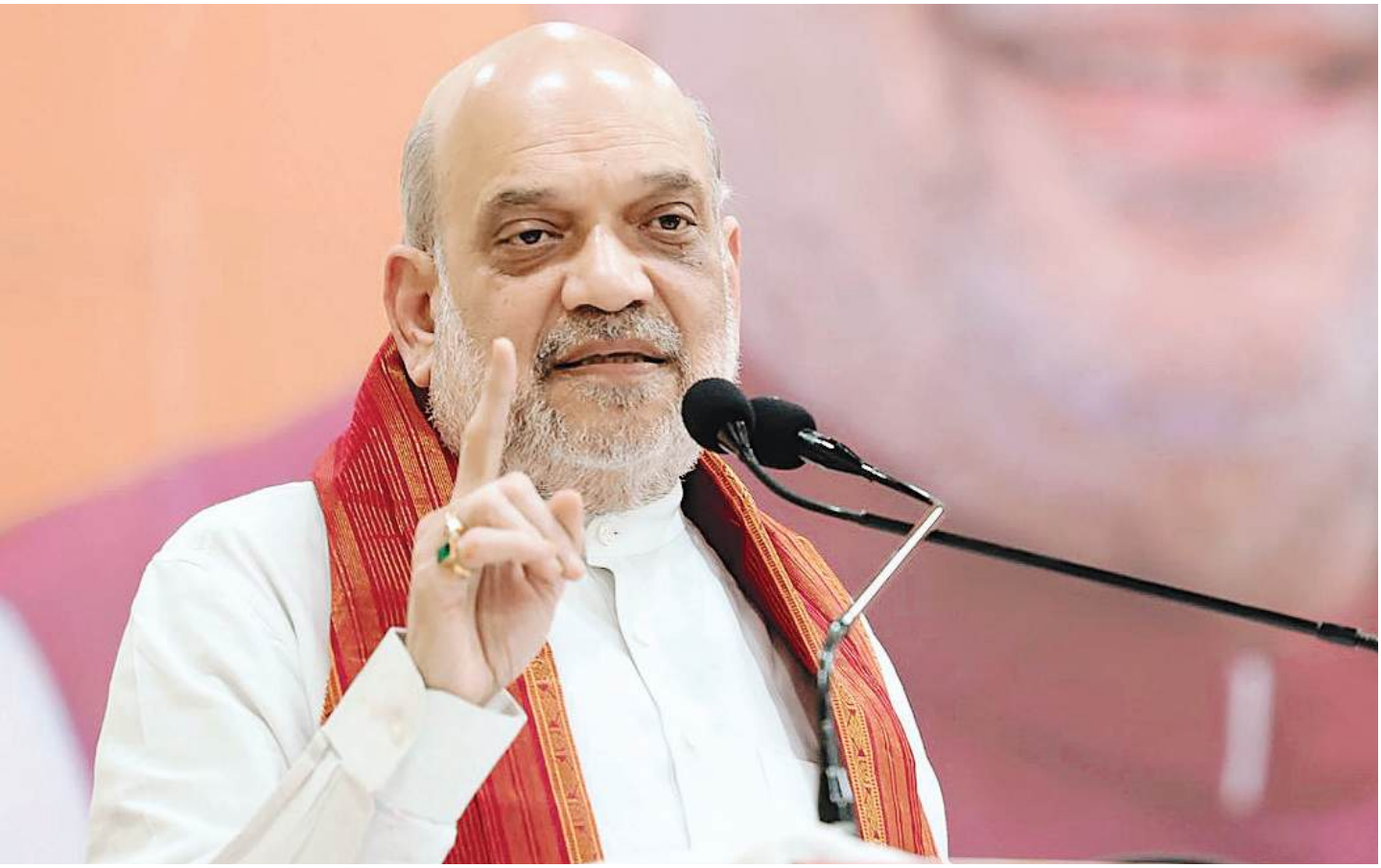

‘वंदे मातरम्’ स्वतंत्रता, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का सबसे शक्तिशाली जयघोष : श्री अमित शाह

सहकार जागरण टीम

- वंदे मातरम् गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई विशेष चर्चा
- वंदे मातरम् राष्ट्र के प्रति समर्पण का माध्यम पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा
- वंदे मातरम् मां भारती के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली एक अमर कृति

वंदे मातरम् कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। जब इसकी रचना हुई, तब इसकी जरूरत जितनी थी, आज भी उतनी है। उस समय वंदे मातरम् देश को आजाद बनाने का कारण बना, जबकि अमृत काल में वंदे मातरम् देश को विकसित और महान बनाने का नारा बनेगा। ये बातें केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में विशेष चर्चा की शुरूआत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् पर चर्चा और इसके प्रति समर्पण की जरूरत इस गीत की रचना करते समय भी थी, आजादी के आंदोलन के समय भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत बनेगा तब भी होगी।

वंदे मातरम् को मां भारती के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली एक अमर कृति बताते हुए श्री शाह ने कहा कि कुछ लोग वंदे मातरम् के महिमामंडन को पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। लेकिन वंदे

मातरम् सिर्फ पश्चिम बंगाल और भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनियाभर में जहां भी आजादी के दीवाने थे, वे अपनी गुप्त बैठकों में भी वंदे मातरम् का गान करते थे। आज भी जब सरहद पर हमारा जवान और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस का जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, तब उसके मुंह पर वंदे मातरम् का ही मंत्र होता है।

वंदे मातरम् गीत को भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने, आजादी का उद्घोष और आजादी के संग्राम का प्रेरणास्रोत बताते हुए केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत के शहीदों को अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए अगले जन्म में फिर से मां भारती के लिए बलिदान देने की प्रेरणा वंदे मातरम से ही मिलती है। कई मनीषियों को हमारे चिर पुरातन देश को सदियों तक अपनी संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी वंदे मातरम् से ही मिली। वंदे मातरम् पर हो रही चर्चा, महिमामंडन और गौरवगान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां वंदे मातरम् के महत्व को भी समझेंगे और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आधार भी बनाएंगे।

वंदे मातरम् की रचना में बहुत बारीकी से हमारी मूल सभ्यता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश की मां के रुप में कल्पना कर उसकी आराधना करने की हमारी परंपरा को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा पुनर्स्थापित करने का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि उस वक्त की सरकार ने इसे रोकना चाहा, इसके गान पर प्रतिबंध लगाया। वंदे मातरम् बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन फिर भी उन सारे प्रतिबंधों को पार कर इस गीत ने बिना किसी प्रचार के हर व्यक्ति के मन को छुआ और गीत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रसार हुआ। वंदे मातरम् एक प्रकार से भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों के पुनर्जागरण का मंत्र बन गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि गुलामी के कालखंड में हमारे कई मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केंद्र कृषि और शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया गया लेकिन हमारी संस्कृति के भाव को हमारे जनमानस से कोई नहीं मिटा सका। उस

वक्त जरूरत थी उस भाव को जागृत करने और पुनर्संगठित करने की और उसी वक्त बंकिम बाबू ने वंदे मातरम् की रचना की। इसे न अंग्रेज रोक सके और न उस सभ्यता को स्वीकार करने वाले लोग रोक सके। वंदे मातरम् ने एक ऐसे राष्ट्र को जागरूक किया जो अपनी दिव्य शक्ति को भुला चुका था। वंदे मातरम् ने राष्ट्र की आत्मा को जागृत करने का काम किया।

भारत को एकसूत्र में जोड़ने वाला मंत्र उसकी संस्कृति को बताते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि इसी के कारण वंदे मातरम् के उद्घोष ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार स्थापित करने का काम किया। आज पूरा देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि हमारी मां का रूप है और हम उसका भक्ति गान भी करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम है। वंदे मातरम् की रचना में हमारे जीवन में भारत माता की कल्पना के योगदान का भावना के साथ वर्णन किया गया है। इसमें भारत माता को जल, फल और समृद्धि की दायिनी बताया गया है, भारत माता को पुष्पों से शोभित, मन को प्रफुल्लित करने वाली और सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का स्वरूप बताया गया है। एक प्रकार से हमारी समृद्धि, सुरक्षा, ज्ञान और विज्ञान भारत मां की ही कृपा और आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेधा हमें भारत मां की कृपा और देश की मिट्टी ही दे सकती है, इसीलिए इसे बारंबार प्रणाम करना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि मातृभूमि ही हमें पहचान, भाषा देती है, सभ्य जीवन जीने की संस्कृति का आधार बनाती है और हमारे जीवन को ऊपर उठाने का अवसर देती है। मातृभूमि से बढ़कर कुछ नही हो सकता और इस चिरपुरातन भाव को बंकिम बाबू ने पुनर्जीवित किया। गुलामी के घनघोर रात्रि जैसे कालखंड में बिजली के प्रकाश की तरह वंदे मातरम ने जन-जन के मन में गुलामी की मानसिकता छोड़कर स्वराज की प्राप्ति का जोश जगाने का काम किया। आजादी के आंदोलन के हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने शहीद होते हुए अंतिम शब्द वंदे मातरम् ही बोले।

देश में लोकतंत्र की जड़े बहुत मजबूत होने की बात कहते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल से 100 साल तक के कालखंड को 'अमृत काल' का नाम दिया है। उन्होंने देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा है कि आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक के इस कालखंड को हम चुनौती के रूप में लेंगे। जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, हमारा देश पूरे विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। यह 140 करोड़ भारतीयों का सकंल्प है, जो पूरा होकर रहेगा। यह देव योग ही है कि जब हम अमृत काल मना रहे, तभी वंदे मातरम् का 150वां साल आया है। इसके माध्यम से हम राष्ट्रभक्ति जगाने का काम करेंगे।■

सहकारी समितियों के सशक्तीकरण में प्रधानमंत्री की 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प की अहम भूमिका

सहकार जागरण टीम

'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए अनेक पहलें की हैं । आगामी पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों और गांवों को आच्छादित करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना का अनुमोदन ऐसी ही एक पहल है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार देश भर में दिनांक 15 नवंबर 2025 तक कुल 30,083 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत किए जा चुके हैं। 15,793 डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को आर्थिक और बुनियादी रूप से सशक्त किया गया है। इन नव-पंजीकृत प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) / डेयरी सहकारी समितियों, मात्स्यिकी सहकारी समितियों को कई तरह से सहयोग किया जाता है। यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी।

अपने उत्तर में उन्होंने बताया कि नए रजिस्ट्रेशन वाले पैक्स के सदस्यों, सचिवों और निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद और नाबार्ड के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है । एनसीसीटी ने 153 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जिसमें एमपैक्स के 6817 सहकारी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है इसके साथ ही पैक्स कंप्युटरीकरण परियोजना के अधीन नई ईआरपी सॉफ्टवेयर अपनाने और उसका प्रबंधन करने के लिए पैक्स को सहयोग करने हेतु कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। इसमें ईआरपी के प्रयोग, डेटा प्रविष्टि और लेखांकन, ऋण, प्रापण और वितरण जैसे मॉड्यूल्स पर पैक्स कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा सुगम अंगीकरण हेतु नियमित वेबिनार, हेल्पलाइन और क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोगकर्ता मैनुअल शामिल हैं।

डेयरी सहकारी समितियों के लिए एनडीडीबी से सहायता जाती है, जिसमें इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देना, पशु स्वास्थ्य, प्रजनन, फीड और चारा, शीतागार, और डिजिटल उपकरण आदि प्रदान करना शामिल है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) से मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सहायता में प्रशिक्षण सहित केज कल्चर, बायोफ्लॉक अंगीकरण, अवसंरचना अनुदान और क्लस्टर-आधारित आद्रभूमि प्रबंधन शामिल है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अधीन वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 के दौरान 6,000 नई मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा एनएफडीबी प्रदान कर रहा है। इसमें प्रत्येक नव-स्थापित मात्स्यिकी सहकारी समितियों को स्थापना, अनुरक्षण और सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए 3.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। 34 राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 1,225 नव-स्थापित सहकारी समितियों को प्रति समिति, 3.00 लाख रुपये के वित्तीय अनुदान द्वारा सहायता प्रदान की गई है ।

डिजिटल सिस्टम का निर्माण

सहकारिता में डिजिटल प्रणाली को मजबूत बनाने संबंधी पूछे प्रश्नों के लिखित उत्तर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह ने बताया कि मंत्रालय ने देश में डिजिटल सहकारी सिस्टम के निर्माण के अनेक उपाय किए हैं । पारदर्शिता और लेखांकन में सुधार के लक्ष्य से पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के माध्यम से सभी कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना ऐसी ही एक पहल है। यह प्लेटफॉर्म क्रेडिट और गैर-क्रेडिट, दोनों कार्यों के एंड-टू-एंड डेटा को कैप्चर करता है और रियल-टाइम अभिलेखीकरण और प्रचालन सटीकता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर, कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से पैक्स प्रदर्शन में सुधार लाता है। इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में सुधार आता

है जिससे ऋणों का त्वरित संवितरण होता है, लेनदेन लागत घटती है, भुगतान असंतुलनों में कमी आती है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है। इसका लक्ष्य किसानों के बीच पैक्स के प्रति विश्वसनीयता को बढ़ाना है। इस परियोजना के अधीन नाबार्ड और सिस्टम इंटिग्रेटर द्वारा पैक्स को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की गई। सॉफ्टवेयर में 22 मॉड्यूल्स दिए गए हैं जिसमें सदस्यता, ऋण, थ्रिफ्ट जमा, बचत, सावधि जमा, पिग्मी जमा, लॉकर, क्रय-विक्रय, भांडागारण, प्रापण, निवेश, उधार, आस्तियां, ऑडिट, शासन, रिपोर्ट निमार्ता, सांख्यिकी, लीगेसी दस्तावेज शामिल हैं ।

आरसीएस कार्यालय हुए कंप्युटरीकृत

देश में सहकारिता मजबूत बनाने के लिए आरसीएस कार्यालयों के कंप्युटरीकरण के प्रश्न के उत्तर में सहकारिता मंत्री श्री शाह ने बताया कि डिजिटल सहकारी तंत्र को पैक्स के अलावा व्यापक सहकारी तंत्र में विस्तारित किया जा रहा है । कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का कंप्युटरीकरण, बहुराज्य सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के आरसीएस कार्यालयों के कंप्युटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित योजना कागजरहित, पारदर्शी और समयबद्ध विनियामक अंतःक्रियाएं सक्षम बनाती हैं । आरबीआई द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए अनुमोदित एक साझा सेवा इकाई- सहकार सारथी की स्थापना, आधुनिक प्रौद्योगिकी सेवाओं के माध्यम से वित्तीय और ऑडिट प्रबंधन को सशक्त करती है। आरबीआई एकीकृत ऑम्बड्समैन योजना के अधीन सहकारी बैंकों की ऑनबोर्डिंग जवाबदेही और शिकायत निवारण में वृद्धि लाती है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 24 जुलाई, 2025 को लॉन्च की गई सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क, डिजिटल मानदंडों जैसे ऑडिट अनुपालन, प्रचालनात्मक प्रदर्शन और वित्तीय शक्ति का उपयोग करके सहकारी समितियों का उद्देश्यपूर्ण आकलन कर पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है ।

सहकारिता मंत्रालय कृषि और ग्रामीण आजीविका में शामिल सहकारी समितियों को प्रोत्साहन और सहायता उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है। नीति-संबंधी पहलः पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन में संशोधन से शासन और पारदर्शिता में सुधार हुआ है। महिलाओं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ अधिक समावेशी, और व्यापक सदस्यता को वैधानिक बनाते हैं।

बैंकिंग और ऋण से संबंधित पहल करते हुए सहकारी बैंकों के लिए शाखा नेटवर्क का विस्तार करने, डोरस्टेप बैंकिंग का विस्तार करने, उच्च आवास और स्वर्ण ऋण सीमा का लाभ उठाने जैसी योजनाओं में भाग लेने के लिए विनियामक छूट और सक्षम उपायों सहित कृषि और ग्रामीण आजीविका सहकारी समितियों के लिए ऋण प्रवाह में सुधार करना शामिल है।

सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने संबंधी सवाल के जवाब में श्री शाह ने बताया कि एक करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना, न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करना और 31 मार्च 2024 से पहले स्थापित नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए रियायती 15 प्रतिशत कर की दर शुरू करने जैसी प्रमुख कर राहत उपाय शामिल हैं।■

सहकारी समितियों में पारदर्शिता और दक्षता के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क

सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं के साथ पैक्स से लेकर अपेक्स (शीर्ष) के बीच प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस को आधार बनाया जाएगा। प्राथमिक सहकारी समितियों को क्षेत्रवार और राज्य, जिला, ब्लॉक-वार रैंक प्रदान किया जाएगा। इस तरह का फ्रेमवर्क बनाने की शुरूआत 24 जनवरी 2025 को कर दिया गया था। राज्य, संघ राज्यक्षेत्र की सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस), राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (एनसीडी) पोर्टल के माध्यम से सात क्षेत्रों की प्राथमिक सहकारी समितियों की रैंकिंग तैयार की जा सकेगी। यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

प्राथमिक सहकारी समितियों के बीच यह रैंकिंग फ्रेमवर्क समितियों के भीतर पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करता है। इससे उनकी कार्यप्रणाली की विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धी क्षमता में भी सुधार करता है ।

यह रैंकिंग फ्रेमवर्क राज्य, संघ राज्यक्षेत्र आरसीएस को संपरीक्षा अनुपालन, परिचालन कार्यकलापों, वित्तीय निष्पादन, अवसरंचना और सामूहिक रूप से 100 अंकों के लिए भारित मूल पहचान सूचना सहित प्रमुख मापदंडों पर आधारित सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है ।

सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क, सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने, सहकारी समितियों को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि, निष्पादन के लिए बेंचमार्क और प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इस रैंकिंग फ्रेमवर्क का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों की सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए किया जा सकता है, ताकि अन्य समितियां इन सर्वोत्तम प्रथाओं को सीख सकें और अंगीकार कर सकें ।

बस्तर ओलंपिक समारोह में बोले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

अगले पांच वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा बस्तर

'जिस बस्तर में पहले लगते थे 'लाल सलाम' के नारे, अब गूंज रहा 'भारत माता की जय'

सहकार जागरण टीम

- **बस्तर सहित पूरे भारत से 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जायेगा नक्सलवाद**
- **बस्तर का हर गांव सड़क से जुड़ेगा, जहां बिजली होगी और हर पांच किलोमीटर के दायरे में मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह संकल्प लिया है कि पूरे बस्तर और भारत को नक्सलमुक्त कराना है। हमने तय किया था कि 31 मार्च, 2026 से पहले पूरे देश से लाल आतंक को खत्म कर देंगे और यह देश मार्च के अंत तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। अगले 5 साल में बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा। इन संकल्पों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में दोहराया। उन्होंने कहा कि हमें यहीं नहीं रुकना है, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, बिजली, शौचालय, नल से पीने का पानी, गैस सिलिंडर, पांच किलो अनाज और पांच लाख तक का मुफ्त इलाज यहां घर-घर पहुचाना है। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सात ज़िलों का बस्तर संभाग वर्ष 2030 के अंत तक देश का सबसे अधिक विकसित आदिवासी संभाग बनेगा। हिंसा में लिप्त नक्सलियों से अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि अब भी गुमराह होकर हमारे ही जो लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं, वो हथियार डाल दें, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाएं, अपने और अपने परिवार के कल्याण के बारे में सोचें और विकसित बस्तर के संकल्प के साथ जुड़ जाएं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होता, न हथियार उठाने वाले लोगों का, न आदिवासियों और न सुरक्षाबलों का भला होता है। सिर्फ शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है।

नक्सल गतिविधियों को छोड़ आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में आए लोगों के लिए सरकार की पुनर्वास योजना पर श्री शाह ने कहा कि जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और जो नक्सलवाद के कारण घायल हुए हैं, उनके लिए एक बहुत आकर्षक पुनर्वसन योजना भी

> हमारे बस्तर की संस्कृति दुनियाभर में सबसे अधिक समृद्ध संस्कृति है। सभी जनजातियों का खानपान, कला, वाद्य, नृत्य और पारंपरिक खेल सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं, बल्कि पूरे भारत की सबसे समृद्ध विरासत है।
>
> - श्री अमित शाह
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

हम लाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि नक्सलवाद समाप्त हो, क्योंकि नक्सलवादी इस क्षेत्र के विकास पर नाग बनकर फन फैलाए बैठे हैं। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही इस क्षेत्र में विकास की एक नई शुरूआत होगी और प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में यह सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा।

नक्सलवाद छोड़कर 700 से अधिक युवाओं का बस्तर ओलंपिक 2025 से जुड़ना गर्व की बात

श्री शाह ने कहा कि हमने अगले पांच साल में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का संकल्प लिया है। अगले वर्ष नवंबर-दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक-2026 के समय तक पूरे भारत और छत्तीसगढ़ से लाल आतंक समाप्त हो चुका होगा और नक्सलमुक्त बस्तर आगे बढ़ रहा होगा। श्री शाह ने कहा बस्तर ओलंपिक-2025 में सात ज़िलों की सात टीमें और एक टीम आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की थी। हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर चुके 700 नक्सलियों को इन खेलों में भाग लेते देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खिलाड़ी के रूप में सामने आकर इन युवाओं ने पूरे देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद के झांसे में आकर उनका पूरा जीवन तबाह हो जाता, लेकिन इन खिलाड़ियों ने भय की जगह आशा चुनी, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुना और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुना है और यही प्रधानमंत्री श्री मोदी की नए भारत और विकसित बस्तर की संकल्पना है।

श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। श्री शाह ने कहा कि बस्तर का हर गांव सड़क से जुड़ेगा, वहां बिजली होगी, प्रत्येक पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं होंगी। सरकार प्राथमिक अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नेटवर्क बनाने का काम करेगी। बस्तर में नए उद्योग, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, भारत में सबसे अच्छा स्पोर्ट्स संकुल और अत्याधुनिक अस्पताल की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने आधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाकर यहां के पारंपरिक गीतों को सहेजने का कार्य किया है। ऐसे कई परंपरागत उत्सव और त्योहार जो नक्सलवाद के लाल आतंक के साए में समाप्त होने की कगार पर थे, उन्हें भी सरकार आगे बढ़ा रही है। ■

सहकारी भागीदारी से आदिवासी ज़िलों में समग्र विकास

श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वन उपज की प्रोसेसिंग के लिए कोऑपरेटिव आधार पर यूनिट्स लगाए जाएंगे। बस्तर संभाग के सातों आदिवासी ज़िलों में सबसे अधिक दूध उत्पादन होगा और डेयरी के माध्यम से लोगों की आय बढ़ाने वाले ज़िले बनेंगे। श्री शाह ने कहा कि कुपोषण के लिए भी विशेष स्कीम चलाई जाएगी। श्री शाह ने कहा कि बस्तर अब बदल रहा है और बस्तर भय नहीं, बल्कि भविष्य का पर्याय बन चुका है। जहां गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज स्कूल की घंटियां बज रही हैं। जहां सड़क बनाना एक सपना था, वहां आज रेलवे ट्रैक और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं, जहां लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां आज भारत माता की जय के नारे लगते हैं। हम सब विकसित बस्तर के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके मार्गदर्शन ने नक्सली युवाओं को ढांढस भी बंधाया है और हिम्मत भी दी है। समाज के प्रमुखों और समाजसेवकों से अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि जो लोग आज भी हथियार लेकर घूम रहे हैं, वे उन्हें समझाकर समाज की मुख्यधारा में वापस लाने का काम करें।

'सहकार से समृद्धि' की राष्ट्रीय परिकल्पना वास्तविकता में हो रही परिवर्तित

सहकार जागरण टीम

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर असम में आयोजित चौथे सहकारिता मेला का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 'सहकार से समृद्धि' की राष्ट्रीय परिकल्पना, सशक्त वास्तविकता में परिवर्तित हो रही है। वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना को ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारत में वर्ष 2047 तक एक सर्वांगीण विश्वस्तरीय सहकारिता प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक संस्थागत प्रोत्साहन और स्पष्ट रोडमैप तैयार हुआ है।

असम राज्य में सहकारिता क्षेत्र में हो रहे तेज सुधारों की सराहना करते हुए श्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के गतिशील नेतृत्व और राज्य के सहकारिता मंत्री श्री जोगेन मोहन के प्रयासों को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर सक्रिय और प्रभावी क्रियान्वयन के चलते असम प्रमुख राष्ट्रीय पहलों में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।

असम ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के 100 प्रतिशत कंप्युटरीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जहां 800 से अधिक पैक्स ने नए मॉडल बायलॉज को अपनाया है। इस प्रगति से युवाओं और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश के 32 लाख से अधिक सहकार सदस्यों को वित्तीय समावेशन का लाभ भी मिला है।

केंद्रीय मंत्री श्री गुर्जर ने कहा कि असम

सहकारिता के पुनर्जागरण की आधारशिला है महापुरुष माधवदेव और श्रीमंत शंकरदेव की सांस्कृतिक विरासत

अब राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप पूरी तरह अग्रसर है। इसके तहत वर्ष 2026 तक प्रत्येक गांव में एक सहकारी संस्था की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने राज्य के लिए एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सहकारिता-आधारित भविष्य के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने महान संत विभूतियों में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और महापुरुष माधवदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि एकता, समानता और समाज सेवा पर आधारित उनकी शिक्षाएं ही सहकारिता की भावना की मूल आधारशिला हैं।

चौथे सहकारिता मेला के उद्घाटन अवसर पर असम सरकार के सहकारिता मंत्री श्री जोगेन मोहन ने इस मेले को जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण का एक जीवंत मंच बताया। प्रतिभागियों की विशेष रूप से सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर अपशिष्ट को उपयोगी संसाधनों में बदलते हुए आत्मनिर्भरता और अद्भुत नवाचार क्षमता का परिचय दिया है। सहकारी संस्थाएं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से लेकर महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और युवाओं की सफलता तक विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को व्यापक लाभ पहुंचा रही हैं।

राज्य के सहकारिता मेले में 160 सहकारी संस्थाओं की भागीदारी हैं। इसमें हथकरघा, मत्स्य पालन, डेयरी, कृषि तथा युवा एवं महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों जैसे प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हैं। यह मेला स्थानीय उत्पादों, नवाचारों और सहकारिता की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। मेला आगामी दो दिनों तक चला। इसमें प्रदर्शनियां, संवाद और ज्ञान-साझा सत्र आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य राज्य में सहकारिता आधारित विकास को और अधिक प्रोत्साहित करना है।■

वैश्विक कृषि में इफको नैनो फर्टिलाइजर की अफ्रीका तक बढ़ी मांग

सहकार जागरण टीम

इफको 93 लाख टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन करके देश की हरित क्रांति का एक स्तंभ बन गया है। आज ब्राजील, अमरीका, ओमान, जोर्डन और दुनिया के 65 देशों में इफको के नैनो यूरिया और डीएपी का निर्यात होता है। देश की प्रमुख सहकारी संस्था इफको की उपलब्धियों को बयां करने वाले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के इन प्रेरणादायी विचारों को आत्मसात करते हुए इफको नैनो फर्टिलाइजर अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना पहुंच गया है। भारत और अफ्रीका के बीच कृषि सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोकॉ ने इफको द्वारा विकसित नैनो उर्वरक कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। बोत्सवाना की मिट्टी और मौसम के हिसाब से एडवांस्ड नैनो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी के जरिए स्थानीय स्तर पर नैनो फर्टिलाइजर के उत्पादन की यह पहल यह इफको के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बोत्सवाना के कृषि क्षेत्र के लिए यह बड़ा कदम है, जिससे यह सिद्ध होता है कि नैनो उर्वरक तकनीक दूसरे महाद्वीपों में भी कृषि बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत की मिट्टी से लेकर बोत्सवाना के खेतों तक इफको की नैनो उर्वरक तकनीक यह साबित कर रही है कि जब नवाचार और सहकारिता एक साथ आते हैं, तो कृषि परिदृश्य बदल देने वाले परिणाम सामने आते हैं। इफको नैनो फर्टिलाइजर का बोत्सवाना में लॉन्च प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि', यानी 'सहयोग से खुशहाली' का एक जीवंत उदाहरण है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि किसानों की क्षमताओं को मजबूत करने और सतत कृषि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे वैश्विक सहयोग की ताकत को दिखाती है और साझा तरक्की और खुशहाली को बढ़ावा देती है।

भारत और अफ्रीका के बीच बढ़ा कृषि सहयोग, बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने इफको के नैनो उर्वरक कार्यक्रम का किया औपचारिक शुभारंभ

बोत्सवाना में नैनो उर्वरक कार्यक्रम का क्रियान्वयन इफको और देश के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं विकास संस्थान (नार्डी) एवं वहां की स्थानीय कंपनी 'लोन ट्रेंड्स' की त्रि-पक्षीय साझेदारी के माध्यम से किया जा रहा है। इस साझेदारी के तहत नैनो उर्वरक तकनीक को बोत्सवाना की मिट्टी, फसल पैटर्न और स्थानीय जलवायु की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया गया है। किसानों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि तकनीक का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके और बोत्सवाना में टिकाऊ एवं सुदृढ़ कृषि प्रणालियां विकसित की जा सकें। नैनो फर्टिलाइजर्स के बोत्सवाना पहुंचने से वहां कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा, जिससे जमींन की पोषण क्षमता बढ़ेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी। इससे लंबे समय तक खाद्य सुरक्षा स्थापित करने में मदद मिलेगी।

बोत्सवाना में लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब इफको का नैनो उर्वरक व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में इफको ने 365.09 लाख नैनो उर्वरक बोतलों की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक है। इफको उत्पादों की यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से तरल नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी की गुणवत्ता और उच्च मांग के कारण हुई है। इफको के प्रबंध निदेशक श्री के.जे. पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, 'इफको, जो पहले से ही अपनी कोऑपरेटिव पहुंच और नवाचार के लिए दुनिया भर में मशहूर है, के लिए यह लॉन्च एक बहुत बड़ा सम्मान हैं। हमारी कामयाबी में एक और वैश्विक उपलब्धि जुड़ गई है। यह अलग-अलग महाद्वीपों में कृषि को नया आकार देने में नैनो-फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका को दिखाता है।'

देश में इफको लगातार अपनी उत्पादन क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू किए गए दो नए संयंत्र अब तरल नैनो डीएपी का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे पांच नैनो इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 9.5 लाख बोतल प्रतिदिन हो गई है। इफको की नैनो उर्वरक पहल देश में टिकाऊ और कुशल कृषि को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय मिशन से भी गहराई से जुड़ी है। ■

पुणे की स्वच्छ सहकारी समिति ने दिखाई नई राह

सहकार जागरण टीम

आमतौर पर भारत में सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करती हैं। वे ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाती रही हैं। लेकिन पुणे स्थित एक सहकारी संस्था ने अपना कार्यक्षेत्र पुणे शहर को चुना और साफ-सफाई के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लिया। इस प्रकार इस संस्था ने अपने कार्य से लोगों को एक नई राह दिखाई है और कार्य करने का एक नया विकल्प पेश किया है।

सन 2008 में स्वच्छ (सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड हैंडलिंग) नामक सहकारी समिति की स्थापना की गई। वर्तमान में इसके 3761 सदस्य हैं। सहकारी संस्थाओं की परंपरागत लाभ केंद्रित दृष्टिकोण की बजाय यह संस्था अपने सदस्यों और कार्यकताओं के व्यापक हित पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कार्य करती है। संस्था ने अपने कार्यों के माध्यम से जहां अपने कार्यकर्ताओं को रोजी-रोटी का एक स्थाई और टिकाऊ अवसर प्रदान किया है, वहीं शहर की सफाई में योगदान देकर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान पेश किया है।

समिति में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं और 93 प्रतिशत से अधिक सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के लोग शामिल हैं। इन्हें औपचारिक रूप से पूणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (पीएमसी) के साथ जोड़ा गया है। संस्था के कार्यकर्ता पीएमसी के साथ मिलकर शहर की साफ-सफाई में योगदान देते हैं। कार्यकर्ता घर-घर जाकर कचरा एकत्रित करते हैं और उसका उचित प्रबंधन करते हैं। इसके बदले में वे शहर के लोगों से यूजर चार्ज लेते हैं। कचर इकट्ठा करने वाले वर्कर हर माह 200 रुपए समिति को प्रदान करते हैं। समिति इस पैसे का इस्तेमाल कार्यकताओं के जीवन में बेहतरी लाने के लिए करती है। खास बात यह है

कि इस पैसे से बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

समिति अपने सदस्यों को सशक्त बनाने और शहर की सफाई के लिए डोर-टू-डोर कूड़े का कलेक्शन कराती है। गीले और सूखे कूड़े को अलग करने का प्रशिक्षण प्रदान कर उसका खाद बनवाती है। इसका इस्तेमाल पौधों के पोषण और जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कूड़े का उचित प्रबंधन करने से पर्यावरण संरक्षण होता है और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। इससे समाज में जागरूकता भी बढ़ती है। लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आते हैं। समिति ने 2300 से अधिक कूड़ा एकत्रित करने वालों को पुणे म्युनिसिपल कापोर्रेशन (पीएमसी) की सफाई सेवा में शामिल कराया है। उन्हें पहचान पत्र, सेफ्टी गियर (ग्लव्स, मास्क), और एक स्ट्रक्चर्ड माहौल दिया। इससे सदस्यों को जीविका का सम्मानजनक व सुरक्षित साधन प्राप्त हो सका। समिति हाउसकीपिंग, पुराने कपड़ों का कलेक्शन और कूड़े से जैविक खाद भी बनाने का प्रोग्राम चलाती रहती है। इससे कूड़े के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का विकास होता है।

समिति शहरी सफाई में इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर को जोड़ने के लिए भारत का सबसे अच्छा मॉडल है। समिति की गतिविधियां यह दिखाती हैं कि एक ही समय में एफि शिएंसी, कॉस्ट सेविंग और सोशल जस्टिस कैसे हासिल किया जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण की दिशा में समिति उल्लेखनीय कार्य कर रही है। समिति के कुल वर्कफोर्स में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। इससे महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास हो रहा है और उनका आर्थिक उन्नयन भी हो रहा है। समिति भारत की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है जिसे सेल्फ-एम्प्लॉयड वेस्ट कलेक्टर और दूसरे शहरी गरीब चलाते हैं। यह पुणे के करीब दस लाख घरों से डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन मैनेज करती है। ■

स्वच्छता से आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी महिला सहकारी समिति

सहकार जागरण टीम

जहां चाह, वहां राह इस कहावत को हकीकत में बदलने का काम किया है बीरगांव (छत्तीसगढ़) की कुछ महिलाओं ने। इन महिलाओं ने उजाला महिला बहुउद्देशीय सहकारी संघ का गठन कर स्वच्छता से सशक्तीकरण तक की एक अनूठी मिसाल पेश की है। संघ की सदस्य महिलाओं ने अपने हाथों से सफाई कर संबंधित इलाके की सिर्फ सूरत ही नहीं, बल्कि अपनी किस्मत भी बदल डाली।

वर्ष 2017 में समिति का गठन किया गया। वर्तमान में 187 महिलाएं इसकी सदस्य हैं। 17 समूहों में ये महिलाएं अपने काम को अंजाम देती हैं। समिति के गठन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को काम, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना था। अब इन्होंने शहर को स्वच्छ रखने के साथ खुद को सशक्त बनाना अपना मिशन बना लिया है।

प्रतिदिन सुबह 6.30 बजे समिति की सदस्य महिलाएं काम में लग जाती हैं। सबसे पहले ये निष्ठा एप पर अपनी हाजिरी लगाती हैं। इसके बाद ई-रिक्शा या ट्राईसायकिल की मदद से घर-घर कचरा इकट्ठा करने का काम करती हैं। इस दौरान ये लोगों को साफ-सफाई, कचरा पृथक्करण और सेहत के प्रति जागरूक करती हैं। इसके बाद 11 बजे से गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग किया जाता है और फिर गीले कचरे से खाद बनाई जाती है। वहीं, सूखे कचरे से अतिरिक्त आय अर्जित होती है।

समिति की सदस्य हर महिला को प्रतिमाह छह हजार रुपए मानदेय प्रदान किया जाता है। समिति सूखे कचरे को बेचकर हर माह 80 से 90 हजार रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित करती है। समिति का साल भर का टर्नओवर 15 लाख 42 हजार रुपए है। इसे कुल 2 लाख 74 हजार रुपए की अतिरिक्त आय होती है। समिति को जो भी लाभ होता है, उसका शत-प्रतिशत वितरण इसकी सदस्य महिलाओं में कर दिया जाता है। समिति का रिजर्व फंड 3 लाख 57 हजार रुपए है। इसे आकस्मिक जरूरतों के लिए सुरक्षित रखा जाता है।

साफ-सफाई में योगदान देकर महिलाओं ने बदली अपनी किस्मत, दूसरों को किया प्रेरित

सामाजिक रूप से हेय माने जाने वाले इस जनहितकारी सहकारी नवाचारी पहल से जहां पहले समिति के सदस्यों को नजर झुकाकर काम करना पड़ता था, वहीं अब उन्हें मान-सम्मान मिलता है। समिति स्वच्छता के साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ा रही है और इसमें लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। समिति की महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है और शहरवासियों में साफ-सफाई की आदत बन रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि शहर में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कम हो रही है। लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। शहर की साफ-सफाई का प्रभाव नागरिकों की सेहत पर भी पड़ा है। अब लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। इससे उनकी आर्थिक बचत भी हो रही है। समिति की इस अभिनव पहल की लोग सराहना कर रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। अब दूसरे लोग भी साफ-सफाई के लिए आगे आ रहे हैं। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है। इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। समिति ने अपने प्रयासों से उम्मीद की एक किरण जगाई है। इस किरण का प्रकाश दिनों-दिन फैलता जा रहा है।■

शिरीष पुरोहित

भारत को विकसित बनाने में युवा सहकारी समितियों की बढ़ेगी भूमिका

सहकारिता में सामूहिकता के साथ काम करने का मॉडल इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बना रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सहकरिता मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी नीतियों के कारण सहकारिता का देश की आर्थिक तरक्की में भी अहम योगदान हो रहा है। देश को विकसित बनाने में युवा सहकारी समितियों की भूमिका अवस्मणीय रहेगी। सहकारी संस्थाएं एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा है, जिसमें सदस्य सामूहिक रूप से अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य करते है। इन संस्थाओं में कौशल विकास और नेतृत्व विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है, ताकि संगठन प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और समाज में अपना योगदान दे सके।

सहकारी प्रबंधन में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एनसीयूआई के अंर्तगत काम करने वाले एनसीडीसी समय समय पर नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करता है। सहकारिता के क्षेत्र में भविष्य की पीढ़ी का सक्रिय योगदान बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए देश में पहली बार त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू की जा रही है। सहकारिता में कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है।

तकनीकी कौशल बिना सहकारी संगठन के सफल संचालन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों के तकनीकि रूप से दक्ष होने पर सहकारिता संगठन अपेक्षाकृत अधिक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सहकरिता के उन्नत विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम पहलों के बावजूद सदस्यों की दक्षता काफी मायने रखती है। सहकारी संगठन का कार्यक्षेत्र चाहे कृषि हो या फिर उत्पादन, इसके लिए सही प्रशिक्षण का महत्व हमेशा रहता है। उत्पादन के साथ ही प्रबंधन और विपणन की कुशलता सहकारी संगठनों की तरक्की का मूल माना गया है।

संगठनात्मक संरचना को समझना- समाज के सामूहिक विकास के लिए गठित सहकारी संगठन का उद्देश्य उसी अवस्था में पूरा किया जा सकता है जबकि संगठन के अंदर की संरचना मजबूत हो, बेहतर संगठन बेहतर परिणामों को अंजाम देता है। सदस्यों और ग्राहको के साथ संवाद करने से समस्याओं का हल होता है। बेहतर संवाद व संचार से सामूहिक निर्णय लेने और कार्यो को टीम के साथ निष्पादित करना संभव होता है।

नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाओं के आयोजन जैसे ई-लर्निंग प्लेटफार्म आदि डिजिटल माध्यम से सदस्यों को कौशल सिखाने से कौशल विकास और उन्नत प्रशिक्षण की प्रक्रिया बनी रहती है। इसके लिए सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

व्यवहारिक अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करने से सरकार और संस्थागत सहायता से सरकारी योजनाओं और एनजीओ के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण को बेहतर तरीके से जरूरत मंद और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है।

सहकारी संस्थाओं में नेतृत्व विकास- सहकारी संस्थाओं में नेतृत्व विकास का मतलब है प्रभावी और जिम्मेदार नेतृत्व का निर्माण करना, जो संगठन को एक दिशा प्रदान कर सके और सदस्यों की जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए नेतृत्व विकास के कई महत्वपूर्ण पहलूओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला बिंदु दृष्टि और योजना को माना गया है। सहकारी संगठनों के सदस्यों को सफल सहकार की भविष्य की योजना बनाने के लिए स्पष्ट सोच के साथ रणनीति तैयार करना अहम पहलू माना गया है।

सामूहिकता से संचालन- संगठन को एकजुट दिशा में ले जाने के लिए एक सफल नेतृत्व की जरूरत होती है। सदस्यों और कर्मचारियों को प्रेरित करना और संगठन के उद्देश्यों के प्रतिबद्धता को बनाए रखना जरूरी है। इससे संगठन के लक्षित उद्देश्यों की प्रतिबद्धता बनी रहती है। सफल सहकारी समितियों के संचालन के लिए एक बेहतर नेतृत्व क्षमता का होना जरूरी है, केवल संचालन ही नहीं प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ सदस्यों को समस्याओं की पहचान करना और उसके समाधान के लिए प्रभावी नीतियों को लागू करना अहम माना गया है।

सहकारिता में सभी सदस्यों की सहभागिता और सदस्यों को साथ लेकर चलना अनिवार्य माना गया है। सहकारी संस्थाओं में कौशल और नेतृत्व विकास पर ध्यान देना उनकी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल संगठन को मजबूत बनाता है, बल्कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समाज को भी सशक्त करता है। सरकार, एनजीओ और सहकारी संस्थाओं को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए।■

प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र,
नौगांव, मध्य प्रदेश

खेती में कार्बन एमिशन कम करने और कार्बन क्रेडिट के जरिए किसानों को अतिरिक्त आय देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) ने केरल की कैराली एग्रीकल्चर मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। एनसीयूआई के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉ. सुधीर महाजन, सीईओ श्री प्रदीप और श्री लतीश और कैराली एमएससीएस के दूसरे डायरेक्टर्स भी मौजूद रहे।

एनसीयूआई के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉ. सुधीर महाजन ने कोलंबो में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कृषि सहकारी समितियों के विकास हेतु नेटवर्क (नेडैक) की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भागीदारी की और सस्टेनेबल कोऑपरेटिव मॉडल को मजबूत करने, रीजनल पार्टनरशिप को बढ़ावा देने नेडैक के विजन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। नेडैक के चेयरमैन श्री पंकज कुमार बंसल ने कृषि सहकारिता के बीच क्षेत्रीय सहयोग की बढ़ती अहमियत पर जोर दिया।

एनसीयूआई ने नई दिल्ली के इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (आईआईटीएम) के विद्यार्थियों के लिए 'सहकारिता' पर एकदिवसीय जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां एनसीयूआई के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉ. सुधीर महाजन और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीमती सावित्री सिंह ने सहकारी क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राजीव शर्मा व श्री रितेश दे, और डिप्टी डायरेक्टर श्री अनंत दुबे भी सहभागी रहे।

एनसीयूआई के नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन (एनसीसीई) में सहकारी शिक्षा और विकास में 30वें डिप्लोमा सत्र में सभी 36 प्रतिभागियों ने कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में भागीदारी की, जहां एनसीयूआई की डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीमती सावित्री सिंह ने उन्हें मूलभूत जानकारी दी। पीएमओ के जॉइंट सेक्रेटरी डॉ. के.के. त्रिपाठी ने प्रतिभागियों को 'एकजुट होकर आगे बढ़ना: सहकार से समृद्धि को साकार करना' विषय पर मार्गदर्शन किया।

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) ने अपने नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन (एनसीसीई) के जरिए कृभको के हजीरा इकाई के लिए 'कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट' पर दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें कृभको के 38 अधिकारियों ने भागीदारी कर सहकारी क्षेत्र में हो रहे बहुआयामी पहलों पर अपनी जिज्ञासाओं के सम्यक समाधान के साथ ही व्यावहारिक पहलुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

एनसीयूआई के नेतृत्व में नई दिल्ली में कोऑपरेटिव सेक्टर के डिप्लोमा प्रोग्राम के प्रतिभागियों ने कृभको का दौरा किया और फेडरेशन के कामकाज और भूमिका के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें सीड टेस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में साइंटिफिक टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल और खेती की उत्पादकता बढ़ाने के बारे में बताया गया, जिससे कोऑपरेटिव के नेतृत्व वाले खेती के विकास के बारे में भी प्रैक्टिकल जानकारी मिली और वे कृभको के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क से भी परिचित हुए।

देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का, देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का, आजाद भारत के सपने को सींचा था वंदे भारत की भावना ने, समृद्ध भारत के सपने को सींचेगा वंदे मातरम। उन्हीं भावनाओं को लेकर के हमें आगे चलना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, 2047 में देश विकसित भारत बन कर रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (**CEAS-LMS**) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक : राजीव शर्मा

Postal Registration No: DLHIN/25/A0141
Published on 15.04.2024 Applied for Registration/ Exempted

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ